भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 840
दिनांक 23 जुलाई, 2026

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज से संबंधित पहल

†840. **श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः**
श्री रमेश अवस्थीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज से संबंधित पहलों के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित की गई रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों और विनियामक ढांचे का ब्यौरा क्या है; और
(घ) भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सीसीयूएस से कितने योगदान का अनुमान है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): विद्युत मंत्रालय, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है। तेल और गैस क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) असम, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों की स्थापना के लिए पायलट परियोजनाएं चालू कर रही हैं और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कर रही हैं। इन परियोजनाओं में संवर्धित तेल वसूली (ईओआर), रसायनों का उत्पादन, पेय उद्योग आदि के लिए ड्राई आइस सहित विविध अनुप्रयोग शामिल हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) इन पहलों के एक भाग के रूप में, बीना रिफाइनरी में एक CO_2 कैप्चर प्रदर्शन इकाई स्थापित कर रही है। इसके अलावा, एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी में 72 टन प्रति दिन (टीपीडी) CO_2 कैप्चर प्रदर्शन संयंत्र ने यांत्रिक रूप से पूर्णता प्राप्त कर ली है। कैप्चर किए गए CO_2 का उपयोग पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए करने का प्रस्ताव है।

दिसंबर 2025 में शुरू किए गए सीसीयूएस रोडमैप के अनुरूप, केंद्रीय बजट 2026-27 में सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों के विकास और स्थापना के लिए पांच वर्षों की अवधि में 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

*****